कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं । कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० की भूमिगत खानों द्वारा कोयले का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 64.30 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 1992-93 में 70.36 मिलियन टन किया गया ।

(ग) और (घ) यद्यपि भारत में अनुसंधान संस्थानों द्वारा किसी विशेष खनन प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं किया गया है, अनेक प्रमुख कोयला उत्पादक देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, यू० के०, पोलैंड तथा रूस से सहायता लेकर 1974—93 की अवधि के दौरान कई नई भूमिगत खनन प्रौद्योगिकियों को आरंभ किया गया है । इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां निम्न है : पावर स्पोर्ट उपकरण के इस्तेमाल से यांत्रिकृत लांगवाल माइनिंग तथा सब-लेवल केविंग; गैलरी ब्लास्टिंग पद्धति; साइड डिस्चार्ज लोडर (एस० डी० एल०) तथा लोड हाल डम्पर्स (एल० एच० डी०) के इस्तेमाल द्वारा यांत्रिकृत बोर्ड तथा पिल्लर; डिसैंडिंग शील्ड माइनिंग, आदि ।

(ङ) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० के अधिकारियों का एक तकनीकी दल चीन की यात्रा पर गया है, ताकि कठिन तथा विस्तृत सैंडस्टोन स्थितियों में, जैसी कि कुछ हमारी खानों में भी व्याप्त हैं, भूमिगत लांगवाल मुहानों में छत के प्रबंधन संबंधी चीन की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया जा सके ।

(च) इसमें अन्तर्ग्रस्त लागत तथा प्राप्त की जाने वाली संभावित उत्पादकता का अभी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है ।

Implementation of 'No Work, No Pay' Policy

*271. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Governments are implementing the policy of "no work, no pay" in respect of Government, public sector and local self Government employees of such States;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government proposes to apply the policy at the national level in the near future; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) "No work, no pay" is already the general policy of the Government of India also.

कोयले के बढ़ते मूल्यों का असर

*272. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1991 से देश में कोयले की कीमतों में लगभग 48% वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन और इस्पात उत्पादन में क्रमशः रू० 1.27 प्रति के०डब्ल्यू०एच० और रू० 61.00 प्रति टन की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्रमशः मार्च, 1992 और मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान देश में कोयला उद्योग ने लाभ कमाया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कितना-कितना लाभ कमाया गया;

(ङ) क्या इन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन की लागत में भी कमी आई है, यदि हां, तो प्रतिवर्ष उसमें अनुमानतः कितनी कमी आई है; और

(च) देश में कोयला खनन उद्योग में कुल कितनी पूंजी का निवेश हुआ है तथा इसमें विदेशी पूंजी कितनी है और कर्ज ली गई राशि कितनी है तथा कर्ज पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जाता है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1991 के बाद से कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों में निम्नलिखित वृद्धि प्रभावी की गई है :—

कंपनी	तारीख जब से प्रभावी हुई	औसत कीमत प्रति मि० टन		प्रतिशतता में वृद्धि
		वृद्धि से पूर्व	वृद्धि के बाद	
को०इं०लि०	17-2-93	322*	364	13.04
	19-6-93	364	382	4.9
सिं०को०कं०लि०	17-2-93	388*	434	11.85
	19-6-93	434	452	4.15

(* दिसम्बर, 1991 में निर्धारित की गई कीमतें)

दिसम्बर, 1991 से जून, 1993 तक वृद्धि प्रतिशतता, कोल इंडिया लि० (को०इं० लि०) के मामले में 18.6% और सिंगरेनी

कोलियरीज़ कंपनी लि० (सि०को०कं०लि०) के मामले में 16.5% होने का हिसाब लगाया गया है । 18 रू० प्रति टन की वृद्धि, जोकि दोनों कोयला कंपनियों के मामले में की गई है, वह 19-6-1993 से प्रभावी है और इससे 1.27 पै० प्रति कि० वा० घंटे की वृद्धि विद्युत का उत्पादन किए जाने में और 61 रू० प्रति टन इस्पात का उत्पादन किए जाने में वृद्धि हो जाएगी ।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कोल इंडिया लि० ने 167.07 करोड़ रू० का लाभ कमाया है । इसके 1992-93 के लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेखे लेखा-परीक्षा के अधीन हैं ।

(ङ) जी, नहीं । कोयले की उत्पादन लागत में गिरावट नहीं आई है । को० ई० लि० के लिए (प्रति टन/रू०) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए उत्पादन लागत क्रमशः 301.67 रू० और 333.25 रू० (अनंतिम) रही है ।

(च) को० ई० लि० द्वारा वर्ष 1992-93 तक किया गया निवेश और दिनांक 31-3-93 की स्थिति के अनुसार ऋण की देय बकाया राशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रू० में)

	वर्ष 1992-93 तक निवेश (अनंतिम)	ऋण विदेशी ऋण	रूपये में ऋण
को० ई० लि०	1533.1	485.42	3947.08

वर्ष 1992-93 के दौरान कोल इंडिया लि० ने 345 करोड़ रू० की राशि सरकार को ब्याज प्रभारों के रूप में अदा की । इसमें विदेशी ऋणों पर ब्याज की राशि शामिल है, जोकि बजट के माध्यम से प्राप्त हुआ था ।

Use of Ration Cards

*273. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government propose to discourage the use of ration cards as identity cards for proof of residence and for other purposes;

(b) if so, what are the details of the proposal;

(c) the time by when a decision is likely to be taken in this regard;

(d) whether it is a fact that the Passport, Police or other authorities insist on the production of ration cards as proof of residence; and

(e) if so, what steps Government propose to take in this regard if ration cards of PDS consumers of certain categories are to be discontinued ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (e) Ration cards are issued by State Governments/UT Administrations to enable consumers to draw commodities supplied through the Public Distribution System and are not intended to confer any other benefit. However, other Government agencies may require production of ration card as proof of residence. There is no proposal under consideration of Central Government either to prevent the use of ration cards for proving residence in a particular address or to deny issue of ration cards to any class or category of customers.

Agreement with China on Mining Technology

*274. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether Government have signed/ arrived at an agreement with China to share/ seek coal mining technology during the recent visit of Coal India Ltd.'s Chairman (Shri S. K. Chowdhary) to China;

(b) whether it is a fact that China was offering its technology at a more affordable price to India as compared to U. K., France, erstwhile USSR and Poland;

(c) whether it is also a fact that C. I. L. in return for China's underground mining technology was willing to part with its relatively advanced open-cast mining technique; and

(d) The time when the Chinese team was visiting India for this purpose, and whether the Indian team's programme to that country under the leadership of C. & M. D. of the Central Mine and Planning Design Institute has been finalised, if so, when and the composition thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (d) During the recent UNIDO sponsored visit of Chairman, Coal India Limited to China, only preliminary discussions were held with Chinese counterparts to share/ seeking coal mining technology. To identify the specific areas of possible co-operation, a team from Coal India is presently visiting China under the leadership of Chairman and Managing Director, Central Mine Planning and